Panchayati Raj Institutions (PRIs)

पंचायती राज संस्थाएँ

* 1952 → CDP (Community Development Programme)
* 1957 → CDP review → Balwant Rai Mehta Committee
* 1959 → Balwant Rai Mehta Comm. Report
  → Rajasthan (Nagore) >> Andhra Pradesh
* 1989 → 64th Amendment >> → 1992 (73rd Amendment)
  * Article 243 (Panchayati Raj System)
  * Part IX

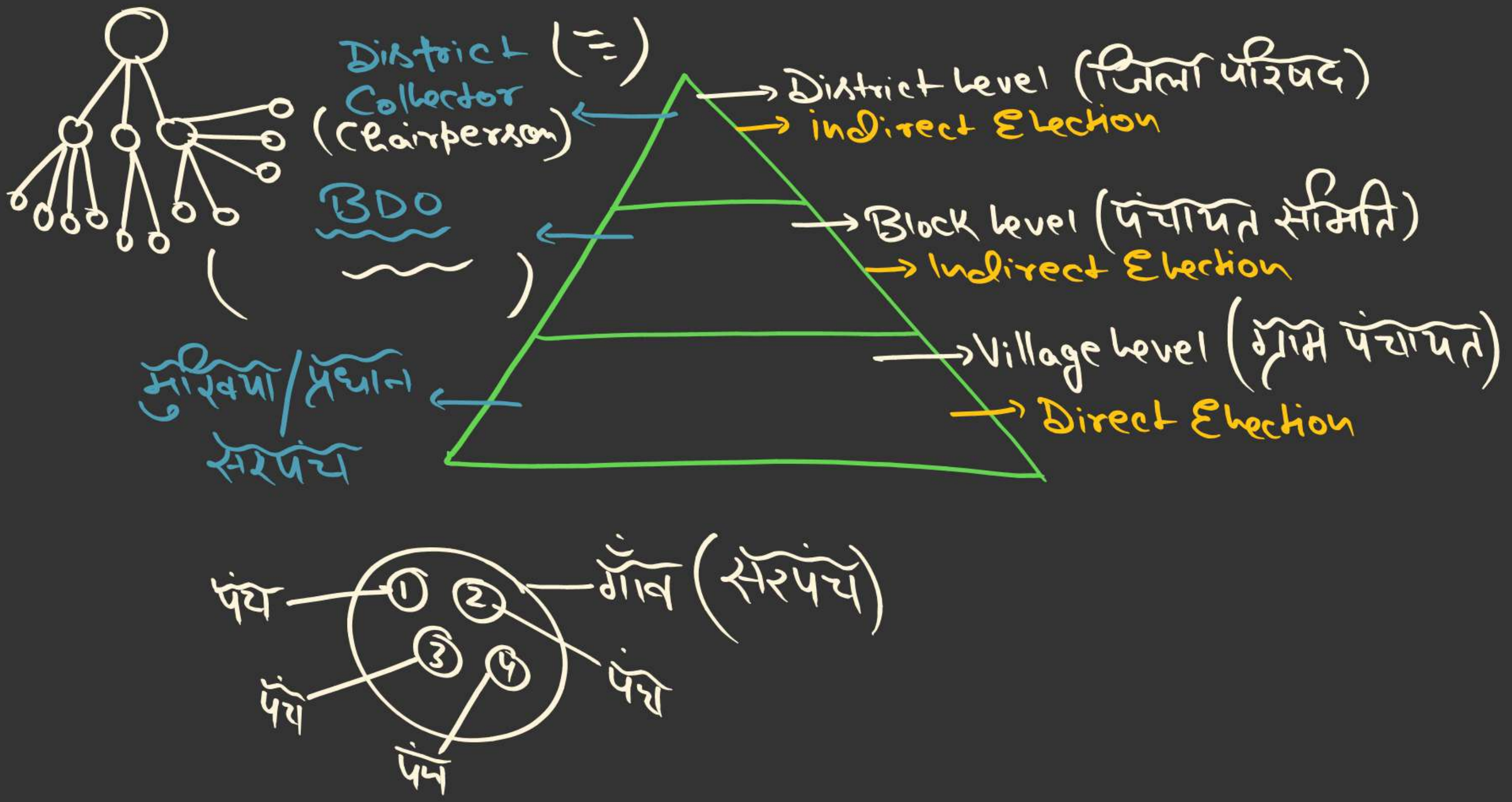
District (=)
Collector
(Chairperson)
BDO
सुरक्षा/प्रधान
सरपंच
District level (जिला परिषद)
→ indirect Election
Block level (पंचायत समिति)
→ Indirect Election
Village level (ग्राम पंचायत)
→ Direct Election
पंच
1
2
3
4
पंच
पंच
पंच
गाँव (सरपंच)

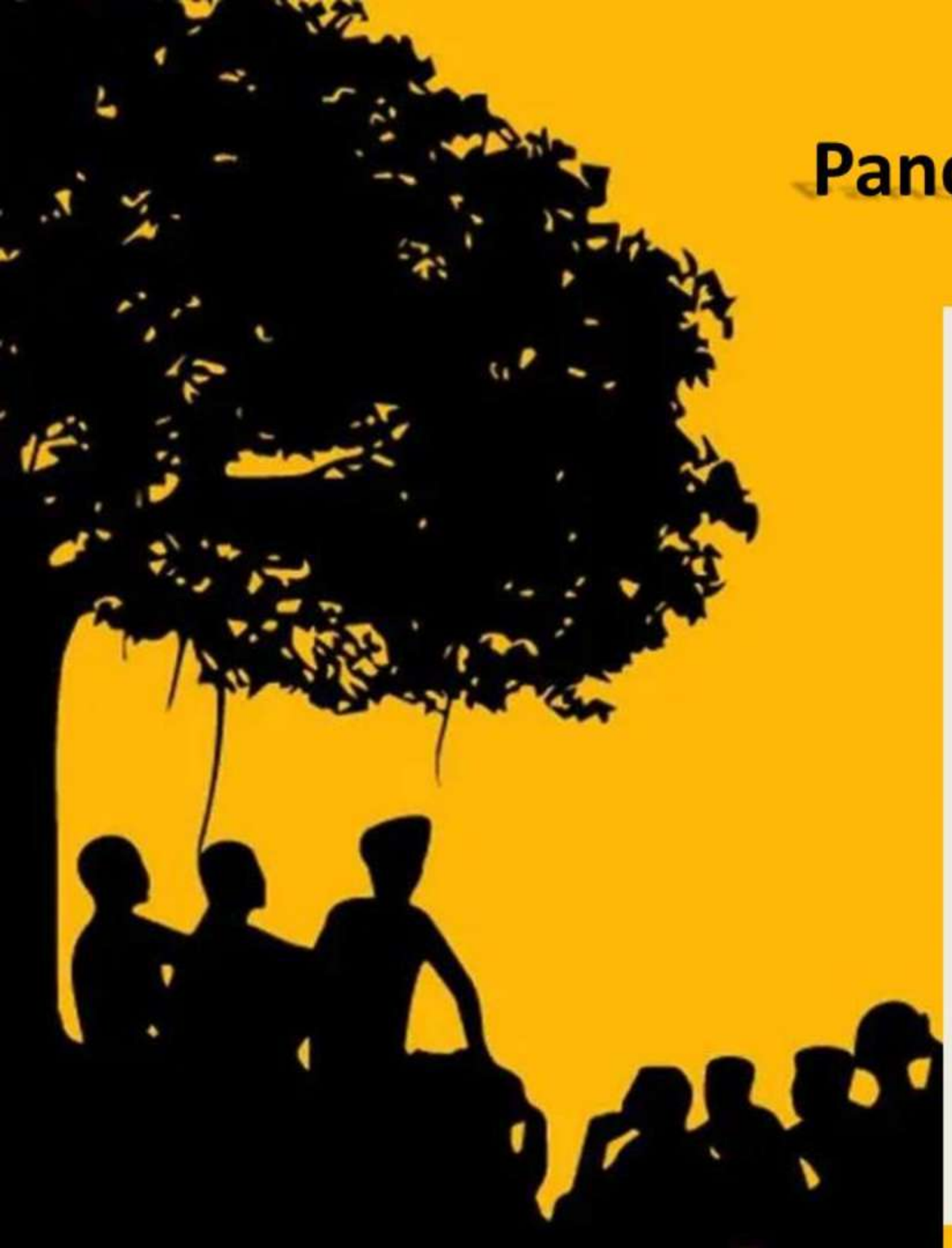

Panchayati Raj Institutions (PRIs)

- Panchayati Raj Institutions (PRIs) are India's rural local self-governance system run by elected representatives.
- पंचायती राज संस्थाएँ (PRIs) ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली हैं, जिन्हें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संचालित करते हैं।
- They function as the third tier of government to strengthen grassroots democracy.
- ये सरकार के तीसरे स्तर के रूप में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करती हैं।
- It was constitutionalised through the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992.
- इसे 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया था।

Evolution of Panchayati Raj (पंचायती राज का विकास)

Balwant Rai Mehta Committee
बलवंत राय मेहता समिति (1957)

- Panchayat Samiti and Zilla Parishad: constituted with indirectly elected
- पंचायत समिति और जिला परिषद: अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों से गठित।
- Chairman of the Zilla Parishad: District collector
- जिला परिषद का अध्यक्ष: जिला कलेक्टर
- Most Indian states set up PRIs by the mid-1960s based on the Balwant Rai Mehta Committee's recommendations.
- बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर 1960 के मध्य तक अधिकांश राज्यों में PRIs स्थापित की गईं।
- Rajasthan was the first state in India to establish PRIs in the year 1959 (Nagore village)
- राजस्थान भारत का पहला राज्य था जिसने 1959 में PRIs की स्थापना की।
- Andhra Pradesh was the second state in India to establish PRIs in the same year 1959
- आंध्र प्रदेश उसी साल 1959 में PRIs स्थापित करने वाला भारत का दूसरा राज्य था।

Evolution of Panchayati Raj (पंचायती राज का विकास)

- The first committee on Panchayati Raj was the Balwantrai Mehta Committee (1957).
- पंचायती राज पर पहली समिति बलवंतराय मेहता समिति थी, जिसे 1957 में नियुक्त किया गया था।
- It was set up to review the Community Development Programme (1952) and National Extension Service (1953).
- इसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) की समीक्षा के लिए बनाया गया था।
- It recommended a three-tier Panchayati Raj system: Gram Panchayat (village), Panchayat Samiti (block), and Zila Parishad (district).
- इसने तीन-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की: ग्राम पंचायत (गांव), पंचायत समिति (ब्लॉक) और जिला परिषद (जिला)।
- These tiers should be organically linked through a device of indirect elections.
- ये स्तर अप्रत्यक्ष चुनावों के ज़रिए आपस में जुड़े होने चाहिए।
- The village panchayat should be constituted with direct elections
- ग्राम पंचायत का गठन सीधे चुनावों से होना चाहिए।

Ashok Mehta committee (1977)

- In 1977, the Janata Government formed the Ashok Mehta Committee on Panchayati Raj.
- 1977 में जनता सरकार ने पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन किया।
- It submitted its report in August 1978 and made 132 recommendations.
- इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और 132 सिफारिशें कीं।
- It recommended replacing the three-tier system with a two-tier system: Zila Parishad and Mandal Panchayat (group of villages with 15,000–20,000 population).
- इसने तीन-स्तरीय व्यवस्था की जगह दो-स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की: जिला परिषद और मंडल पंचायत (15,000–20,000 जनसंख्या वाले गाँवों का समूह)।
- District as first point for decentralization under popular supervision below the state level.
- राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत विकेंद्रीकरण के लिए जिले को पहला बिंदु बनाया जाए।

Ashok Mehta committee (1977)

- Official participation of political parties at all levels of panchayat elections.
- पंचायत चुनावों के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी।
- Compulsory powers of taxation to PRIs to mobilise own financial resources.
- अपने वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए PRIs को अनिवार्य कराधान शक्तियां दी जाएं।
- Regular social audit by a district level agency and by a committee of legislators to ascertain spending mandate.
- खर्च के जनादेश का पता लगाने के लिए जिला स्तरीय एजेंसी और विधायकों की एक समिति द्वारा नियमित सामाजिक ऑडिट।
- Elections should be held within six months from the date of supersession, if any
- यदि कोई हो, तो पद से हटाने की तारीख से छह महीने के भीतर चुनाव होने चाहिए।
- Minister for Panchayati raj in the state council of ministers.
- राज्य मंत्रिपरिषद में पंचायती राज मंत्री।
- Reservation of Seats for SCs and STs on the basis of their population.
- उनकी आबादी के आधार पर SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण।
- Constitutional recognition should be accorded to the PRIs, which will ensure sanctity and stature and an assurance of continuous functioning.
- PRI को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, जिससे पवित्रता और कद सुनिश्चित होगा और लगातार काम करने का आश्वासन मिलेगा।

G. V. K. Rao committee (1985)

- Committee to review the existing "Administrative Arrangements for Rural Development and Poverty Alleviation Programmes".
- मौजूदा "ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था" की समीक्षा करने वाली समिति।
- Zilla Parishad (District level body) should be of pivotal importance in the scheme of democratic decentralisation.
- लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना में जिला परिषद (जिला स्तर का निकाय) का मुख्य महत्व होना चाहिए।
- It suggested creating the post of District Development Commissioner as the CEO of the Zila Parishad and head of all district-level development departments.
- इसने जिला विकास आयुक्त का पद बनाने की सिफारिश की, जो जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो और सभी जिला-स्तरीय विकास विभागों का प्रमुख हो।
- Regular elections to the Panchayati Raj institutions
- पंचायती राज संस्थाओं के लिए नियमित चुनाव

L M Singhvi Committee (1986)

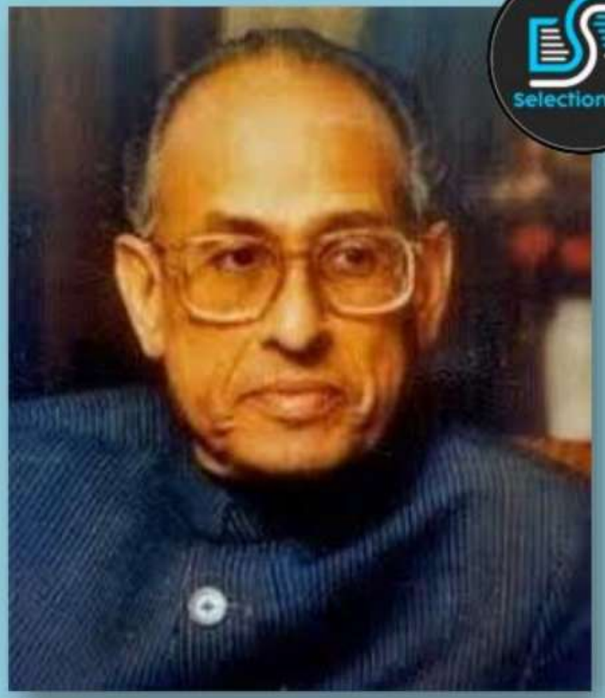

- In 1986, the Rajiv Gandhi Government set up the L.M. Singhvi Committee to prepare a concept paper on strengthening Panchayati Raj for democracy and development.
- 1986 में राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज को लोकतंत्र और विकास के लिए मज़बूत बनाने हेतु कॉन्सेप्ट पेपर तैयार करने के लिए एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया।

Recommedations/सिफारिशें :

- The panchayati Raj institutions should be constitutionally recognized , protected and preserved.
- पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए और उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए।
- Nyaya Panchayat should be established for a cluster of villages.
- गाँवों के समूह के लिए न्याय पंचायतें स्थापित की जानी चाहिए।
- The village panchayats should have more financial resources.
- ग्राम पंचायतों के पास ज़्यादा वित्तीय संसाधन होने चाहिए।
- It recommended setting up judicial tribunals in each state to resolve disputes related to PRI elections, dissolution, and functioning.
- इसने प्रत्येक राज्य में न्यायिक अधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की, ताकि PRI के चुनाव, विघटन और कार्यप्रणाली से जुड़े विवादों का निपटारा हो सके।

Thungon Committee (1988)

- In 1988, a sub-committee of the consultative Committee of Parliament was constituted under the chairmanship of P.K. Thungon.
- 1988 में, संसद की सलाहकार समिति की एक सब-कमेटी पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में बनाई गई थी।

Recommendations/सिफारिशें:

- To examine the political and administrative structure in the district for the purpose of district planning.
- ज़िला प्लानिंग के मकसद से ज़िले में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करना।
- Constitutional recognition to Panchayati Raj bodies.
- पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देना।
- Three-tier system of PRIs with panchayats at the village, block and district levels.
- गांव, ब्लॉक और ज़िला लेवल पर पंचायतों के साथ PRIs की तीन-स्तरीय प्रणाली।
- Zilla Parishad should act as the pivot of planning and development agency in the district.
- ज़िला परिषद को ज़िले में प्लानिंग और विकास एजेंसी के मुख्य केंद्र के रूप में काम करना चाहिए।

Thungon Committee (1988)

- Fixed tenure of five years to PRIs.
- पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पांच साल तय किया गया है।
- The maximum period of super session of a body should be six months.
- किसी संस्था को सुपरसीड करने की अधिकतम अवधि छह महीने होनी चाहिए।
- A detailed enumerations of subjects for Panchayati Raj should be prepared and incorporated in the Constitution.
- पंचायती राज के लिए विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार की जानी चाहिए और उसे संविधान में शामिल किया जाना चाहिए।
- Reservation of seats in all the three-tiers – SC, ST, Women.
- तीनों स्तरों पर सीटों का आरक्षण – SC, ST, महिलाएँ।
- State finance commission should be set-up in each state.
- हर राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए।
- Chief executive officer of the Zilla Parishad- district collector.
- जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी - जिला कलेक्टर।

Gadgil committee (1988)

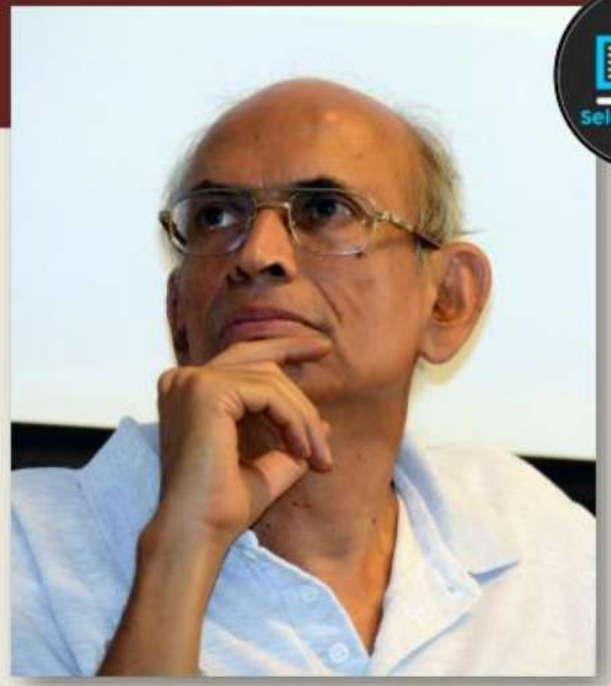

- The Committee on Policy and Programmes.
- पॉलिसी और प्रोग्राम पर कमेटी।
- Constitutional status should be bestowed on the Panchayati Raj institutions.
- पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए।
- Three-tier system of Panchayati Raj with panchayats at the village, block and district levels.
- गांव, ब्लॉक और जिला लेवल पर पंचायतों के साथ पंचायती राज की तीन-स्तरीय प्रणाली।
- Fixed five years term of Panchayati Raj institutions.
- पंचायती राज संस्थाओं का निश्चित पांच साल का कार्यकाल।

Gadgil committee (1988)

- Direct elections for members of the Panchayats at all the three levels.
- तीनों लेवल पर पंचायतों के सदस्यों के लिए सीधे चुनाव।
- Reservation for SCs, STs and women proportionate with their population.
- SC, ST और महिलाओं के लिए उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण।
- Establishment of a State Finance Commission for the allocation of finances to the Panchayats.
- पंचायतों को फाइनेंस के बंटवारे के लिए एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना।
- Establishment of a State Election Commission for the conduction of elections to the panchayats.
- पंचायतों के चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना।

The Committees appointed are as follows:

- Balwant Rai Mehta Committee (बलवंत राय मेहता समिति) (1957)
- Ashok Mehta Committee (अशोक मेहता समिति) (1977)
- GVK Rao Committee (जी. वी. के. राव समिति) (1985)
- L. M. Singhvi Committee (एल. एम. सिंहवी समिति) (1986)
- Thungon Committee (थुंगोन समिति) (1988)
- Gadgil Committee (गाडगिल समिति) (1988)

73rd constitutional Amendment Act of 1992

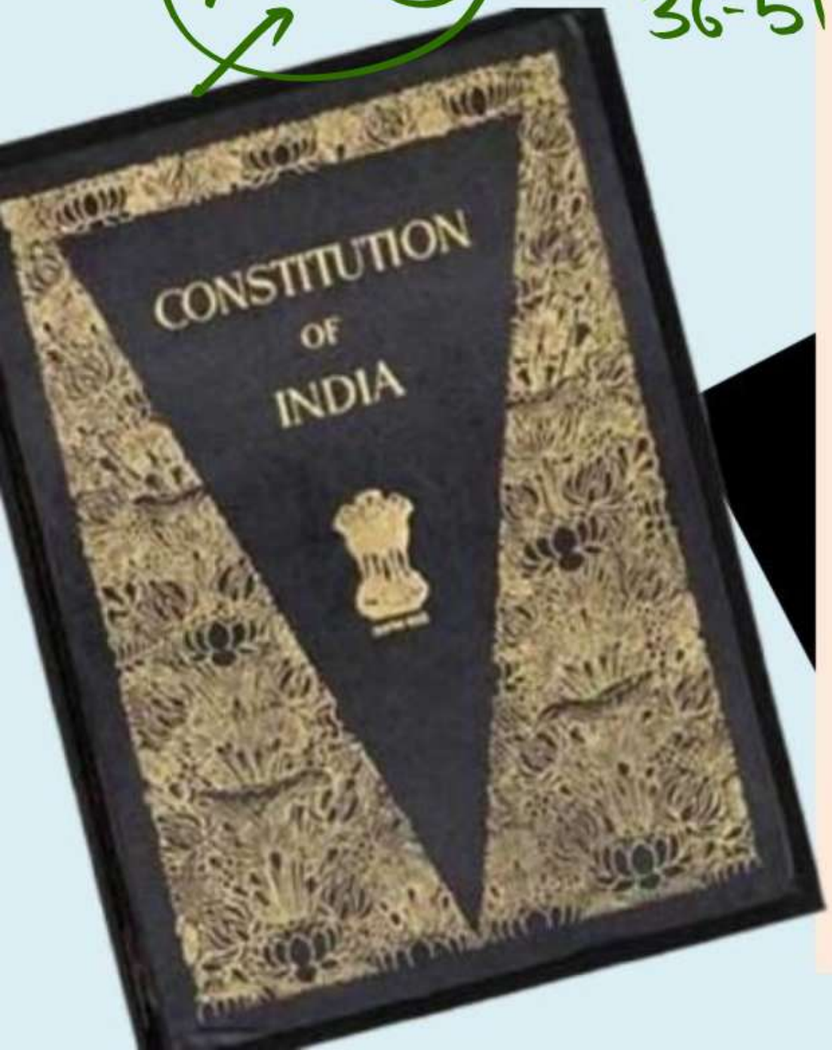

- New part IX to the constitution, eleventh schedule consisting 29 functional items of the panchayats.
- संविधान में नया भाग IX, ग्यारहवीं अनुसूची जिसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक आइटम शामिल हैं।
- Part IX: Article 243 To Article 243 O.
- भाग IX: अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 O तक।
- It emphasized that Article 40 requires empowering village panchayats as self-governing bodies.
- इसने कहा कि अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों को स्वशासी निकाय बनाने के लिए सशक्त करना चाहिए।

73rd constitutional Amendment Act of 1992

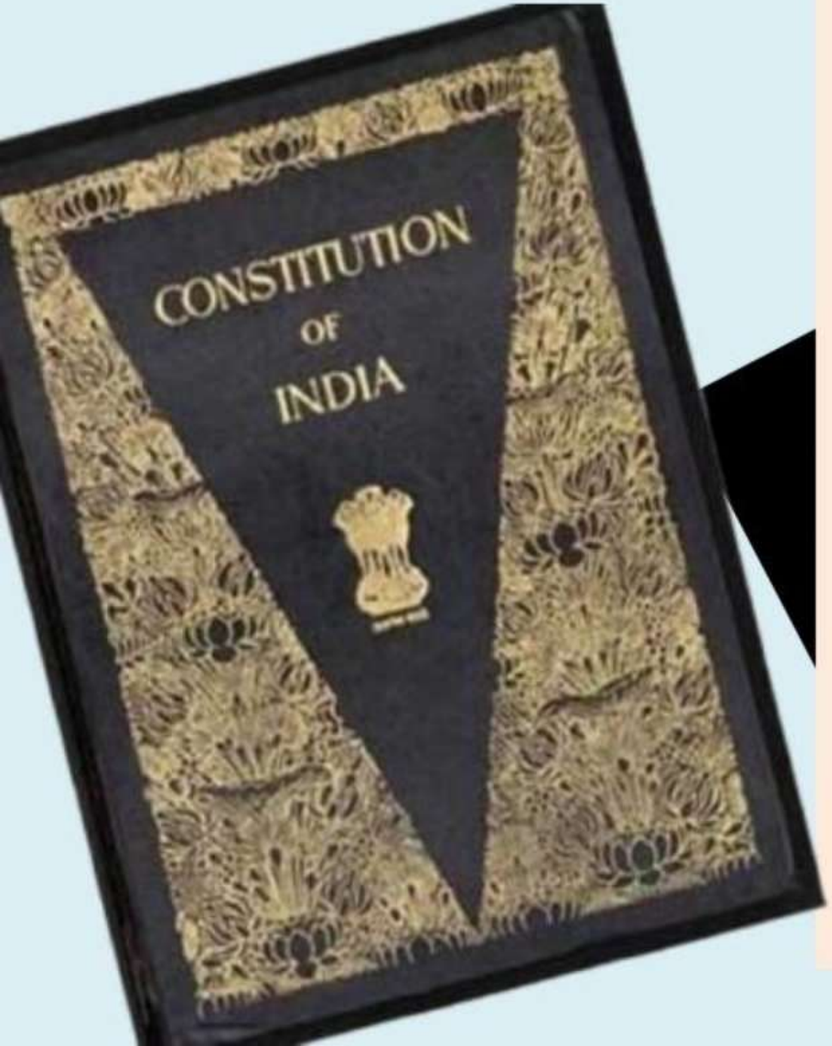

- The act has two parts: compulsory and voluntary.
- इस अधिनियम के दो भाग हैं: अनिवार्य और स्वैच्छिक।
- Compulsory Provisions: must be added to state laws, which includes the creation of the new Panchayati Raj systems.
- अनिवार्य प्रावधान: इन्हें राज्य कानूनों में जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें नई पंचायती राज प्रणालियों का निर्माण शामिल है।
- Voluntary Provisions: on the other hand, are at the discretion of the state government.
- स्वैच्छिक प्रावधान: दूसरी ओर, राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर हैं।

Features of the 73rd Constitutional Amendment Act in Panchayati Raj

Gram Sabha 243A:

Village assembly consisting of all the registered voters within the area of the panchayat.
पंचायत क्षेत्र के सभी रजिस्टर्ड वोटर्स से मिलकर बनी गांव की सभा।

Three-tier System:

At village, intermediate and district level. States with a population less than 20 lakhs may not constitute the intermediate level.
गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर। जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है, वे मध्यवर्ती स्तर का गठन नहीं कर सकते हैं।

Election of members and chairperson (243K): सदस्यों और चेयरपर्सन का चुनाव (243K):

Members at all PRI levels are directly elected; chairpersons at block and district levels are indirectly elected, while the village-level chairperson is chosen as per state rules.
सभी स्तरों पर PRI सदस्यों का चुनाव सीधे होता है; ब्लॉक और जिला स्तर के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और ग्राम स्तर के अध्यक्ष का चयन राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होता है।

Important Article related to Panchayats

Article No.	Subject – Matter (विषय – वस्तु)
Article 243	Definitions / परिभाषाएँ
Article 243A	Gram Sabha / ग्राम सभा
Article 243B	Constitution of Panchayats / पंचायतों का गठन
Article 243C	Composition of Panchayats / पंचायतों की संरचना
Article 243D	Reservation of seats / सीटों का आरक्षण
Article 243E	Duration of Panchayats / पंचायतों की अवधि
Article 243F	Disqualifications for membership / सदस्यता के लिए अयोग्यता
Article 243G	Powers, authority and responsibilities of Panchayats / पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व
Article 243H	Powers to impose taxes by, and funds of the Panchayats / पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियाँ और उनके कोष
Article 243I	Constitution of Finance Commission to review financial position / वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु वित्त आयोग का गठन

Important Article related to Panchayats

Article No.	Subject – Matter (विषय – वस्तु)
Article 243J	Audit of accounts of Panchayats / पंचायतों के खातों का लेखा परीक्षण
Article 243K	Elections to the Panchayats / पंचायतों के चुनाव
Article 243L	Application to Union Territories / संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना
Article 243M	Part not to apply to certain areas / कुछ क्षेत्रों पर यह भाग लागू नहीं होगा
Article 243N	Continuance of existing laws and panchayats / विद्यमान कानूनों और पंचायतों की निरंतरता
Article 243O	Bar to interference by courts in electoral matters / चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक

Reservation of seats (Article 243 D)

- Seats for SCs and STs are reserved in every panchayat in proportion to their population.
- हर पंचायत में SC और ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती हैं।

- At least one-third of all panchayat seats are reserved for women, including SC/ST women.
- कुल सीटों में से कम से कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, जिसमें SC/ST महिलाओं की सीटें भी शामिल हैं।

- The act allows state legislatures to provide reservation of seats or chairperson posts in panchayats if they choose to.
- यह अधिनियम राज्य की विधानसभाओं को पंचायतों में सीटों या अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधान बनाने का अधिकार देता है।

Duration of Panchayats (Article 243 E)

- The act Provides for a five year term of office to the Panchayat at every level from the date of its first meeting.
- यह एक्ट हर लेवल पर पंचायत को उसकी पहली मीटिंग की तारीख से पांच साल का कार्यकाल देता है।
- However it can be dissolved before the completion of its term.
- लेकिन इसे इसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है।

Disqualifications (243 F)

- A person shall be disqualified for being chosen as or for being a member of panchayat if he is so disqualified
- कोई भी व्यक्ति पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य होने के लिए अयोग्य माना जाएगा यदि वह
- Under any law for the time being in force for the purpose of elections to the legislature of the state concerned.
- संबंधित राज्य के विधानमंडल के चुनावों के उद्देश्य से इस समय लागू किसी भी कानून के तहत अयोग्य है।
- Under any law made by the state legislature.
- राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत।
- 21 years to be the minimum age for contesting elections to panchayats.
- पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

State Election Commission for Each State:

- The state legislature can make laws on all matters related to panchayat elections, while the State Election Commission (SEC) conducts elections for Panchayats and Municipalities.
- राज्य विधानमंडल पंचायत चुनाव से जुड़े सभी मामलों पर कानून बना सकता है, और पंचायत व नगर निकायों के चुनाव SEC (राज्य निर्वाचन आयोग) कराता है।

Powers and Functions 243 G:

- State legislatures can give Panchayats the powers they need to function as self-governing bodies.
- राज्य विधानमंडल पंचायतों को इतना अधिकार दे सकता है कि वे स्वशासी संस्थाओं की तरह काम कर सकें।
  - ✓ The preparation of plans for economic development and social justice.
  - ✓ आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी।
  - ✓ They are responsible for implementing schemes of economic development and social justice, including the 29 subjects in the Eleventh Schedule.
  - ✓ वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषय भी शामिल हैं।

Finances 243H

- The state legislature may,
- राज्य विधानमंडल,
- Authorise a panchayat to levy, collect and appropriate taxes, duties, tolls and fees.
- किसी पंचायत को टैक्स, ड्यूटी, टोल और फीस लगाने, इकट्ठा करने और इस्तेमाल करने का अधिकार दे सकता है।
- Assign to a panchayat taxes, duties, tolls and fees levied and collected by the state government
- राज्य सरकार द्वारा लगाए और इकट्ठा किए गए टैक्स, ड्यूटी, टोल और फीस किसी पंचायत को सौंप सकता है।
- Provide for making grants-in-aid to the panchayats from the consolidated fund of the state.
- राज्य के कंसोलिडेटेड फंड से पंचायतों को ग्रांट-इन-एड देने का प्रावधान कर सकता है।
- Provide for the constitution of funds for crediting all money of the panchayats.
- पंचायतों के सभी पैसे जमा करने के लिए फंड बनाने का प्रावधान कर सकता है।

Finance Commission 243 I

- Every five years, the Governor must set up a Finance Commission to review the financial position of Panchayats and give recommendations.
- राज्यपाल हर पाँच साल में एक वित्त आयोग गठित करते हैं, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर सिफारिशें देता है।

Audit of Accounts 243 J

- State legislature may make provisions for the maintenance and audit of panchayat accounts.
- राज्य विधानमंडल पंचायत खातों के रखरखाव और ऑडिट के लिए प्रावधान बना सकता है।

Application to Union Territories 243 L

- The president may direct the provisions of the act to be applied on any union territory subject to exceptions and modifications he specifies.
- राष्ट्रपति इस एक्ट के प्रावधानों को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश पर लागू करने का निर्देश दे सकते हैं, जिसमें वे कुछ छूट और बदलाव बता सकते हैं।
- Exempted States and Areas: The Act does not apply to Nagaland, Meghalaya, Mizoram, and certain tribal or Scheduled Areas.
- छूट वाले राज्य और क्षेत्र: यह अधिनियम नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम तथा कुछ अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता।
- The hill area of Manipur for which a district council exists and
- मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र जिसके लिए एक जिला परिषद है और
- Darjeeling district of West Bengal for which Darjeeling Gorkha Hill Council exists
- पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला जिसके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल है

Bar to interference by courts 243 O

- No panchayat election can be challenged except through an election petition filed before the authority designated by the state legislature.
- पंचायत चुनाव को केवल राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के समक्ष चुनाव याचिका दाखिल करके ही चुनौती दी जा सकती है।

PESA Act of 1996

Objectives of PESA Act

- To extend the provisions of Part IX to the scheduled areas.
- अनुसूचित क्षेत्रों में भाग IX के प्रावधानों का विस्तार करना।
- To provide self-rule for the tribal population.
- जनजातीय आबादी को स्वशासन प्रदान करना।
- To have village governance with participatory democracy.
- भागीदारी लोकतंत्र के साथ ग्राम शासन स्थापित करना।
- To evolve participatory governance consistent with the traditional practices.
- पारंपरिक प्रथाओं के अनुरूप सहभागी शासन प्रणाली विकसित करना।
- To preserve and safeguard traditions and customs of tribal population.
- जनजातीय समुदाय की परंपराओं और रीति-रिवाजों को संरक्षित और सुरक्षित करना।
- To empower panchayats with powers conducive to tribal requirements.
- पंचायतों को जनजातीय आवश्यकताओं के अनुरूप शक्तियाँ प्रदान करना।
- To prevent panchayats at a higher level from assuming powers and authority of panchayats at a lower level.
- उच्च स्तर की पंचायतों को निम्न स्तर की पंचायतों की शक्तियाँ और अधिकार अपने हाथ में लेने से रोकना।

States covered/कवर किए गए राज्य

- PESA applies to 10 states having fifth scheduled areas:

पेसा 5वीं अनुसूची वाले 10 राज्यों पर लागू होता है:

- ✓ Andhra Pradesh
- ✓ Chhattisgarh
- ✓ Gujarat
- ✓ Himachal Pradesh
- ✓ Jharkhand
- ✓ Madhya Pradesh
- ✓ Maharashtra
- ✓ Odisha
- ✓ Rajasthan
- ✓ Telangana

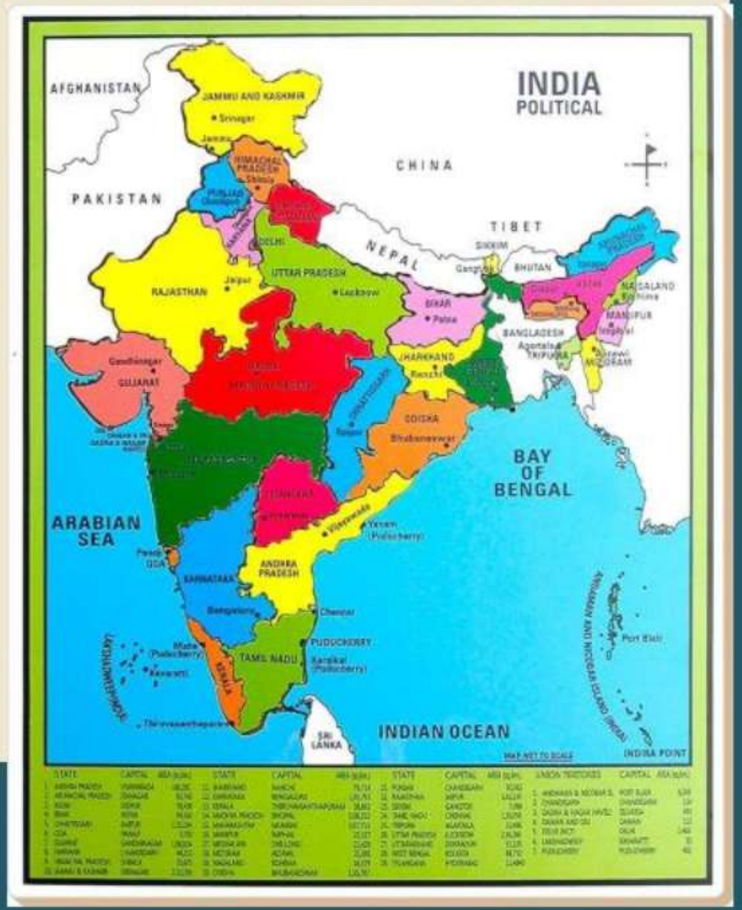

‘Sarpanch Pati’ Practice in India (Proxy Sarpanch)

❑ What is the “Sarpanch Pati” practice?

- A Sarpanch is the elected head of a village panchayat (local self-government body).
- सरपंच एक ग्राम पंचायत (स्थानीय स्वशासन संस्था) का निर्वाचित प्रमुख होता/होती है।
- In many villages, when a woman is elected as sarpanch, her husband or a male relative informally runs the office and makes decisions on her behalf.
- कई गाँवों में जब किसी महिला को सरपंच चुना जाता है, तो उसका पति या कोई पुरुष रिश्तेदार अनौपचारिक रूप से कार्यालय चलाता है और उसके स्थान पर निर्णय लेता है।
- These men are commonly called “Sarpanch Pati”, “Pradhan Pati”, or “Mukhiya Pati.”
- ऐसे पुरुषों को सामान्यतः “सरपंच पति”, “प्रधान पति” या “मुखिया पति” कहा जाता है।
- This makes the elected woman only a figurehead, while the real authority is exercised by the male relative, which undermines women’s political participation.
- इससे चुनी हुई महिला केवल औपचारिक प्रमुख (figurehead) बनकर रह जाती है, जबकि वास्तविक अधिकार पुरुष रिश्तेदार के पास होता है, जिससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी कमजोर होती है।

Government campaign

- The Ministry of Panchayati Raj launched a nationwide campaign titled "Say No To Proxy Sarpanch."
- पंचायती राज मंत्रालय ने "Say No To Proxy Sarpanch" नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया।
- It was launched around International Women's Day (March 8) and runs for several days to raise awareness.
- यह अभियान अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के आसपास शुरू किया गया और जागरूकता बढ़ाने के लिए कई दिनों तक चलाया जाता है।

The campaign aims to

1. Encourage women sarpanches to exercise their own authority./महिला सरपंचों को अपने अधिकारों का स्वयं प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।
2. Raise awareness against proxy leadership in villages./गाँवों में प्रॉक्सी नेतृत्व (Proxy Sarpanch) के खिलाफ़ जागरूकता बढ़ाना।
3. Promote true representation of women in local governance./स्थानीय शासन में महिलाओं के वास्तविक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना।

Why this issue exists यह समस्या क्यों मौजूद है

- Seats in panchayats are reserved for women under the 73rd Constitutional Amendment (1992).
- 73वें संविधान संशोधन (1992) के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं।
- However, due to patriarchal norms, lack of awareness, and social pressure, male relatives sometimes take control of governance decisions instead of the elected woman.
- लेकिन पितृसत्तात्मक सामाजिक मान्यताओं, जागरूकता की कमी और सामाजिक दबाव के कारण कई बार निर्वाचित महिला के स्थान पर उसके पुरुष रिश्तेदार शासन से जुड़े निर्णय लेने लगते हैं।

Why the campaign matters यह अभियान क्यों महत्वपूर्ण है

- Ensures women leaders actually govern rather than acting as proxies.
- यह सुनिश्चित करता है कि महिला नेता वास्तव में शासन करें, केवल प्रॉक्सी (Proxy) के रूप में काम न करें।
- Strengthens grassroots democracy and accountability.
- यह जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और जवाबदेही को मजबूत बनाता है।
- Improves women's political empowerment and leadership at the village level.
- यह ग्राम स्तर पर महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण और नेतृत्व को बढ़ावा देता है।

Campaign Against 'Sarpanch Pati' Practice

What is "Sarpanch Pati" Practice?

- Woman elected as Sarpanch
- Husband/male relative controls the office
- Woman becomes just a figurehead

The Government Initiative

- "Say No To Proxy Sarpanch" Campaign
- Launched on International Women's Day
- Empower Women Sarpanches
- Promote True Leadership

Why It Exists?

- Patriarchal Norms
- Social Pressure
- Lack of Awareness

Campaign Goals

- *Stop Proxy Sarpanch*
- *Encourage Women's Leadership*
- *Strengthen Grassroots Democracy*

Empowering Women in Local Governance